



UKA-27

सामान्य अध्ययन ( टेस्ट - II )  
GENERAL STUDIES (Test - II)

मॉड्यूल - II / Module - II

DTVVF/17-M-GS2

निर्धारित समय: तीन घंटे  
Time allowed: Three Hoursअधिकतम अंक: 250  
Maximum Marks: 250

नाम (Name): Arvind Pratap Singh

क्या आप इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं? हाँ  नहीं 

मोबाइल नं. (Mobile No.):

ई-मेल पता (E-mail address):

टेस्ट नं. एवं दिनांक (Test No. &amp; Date):

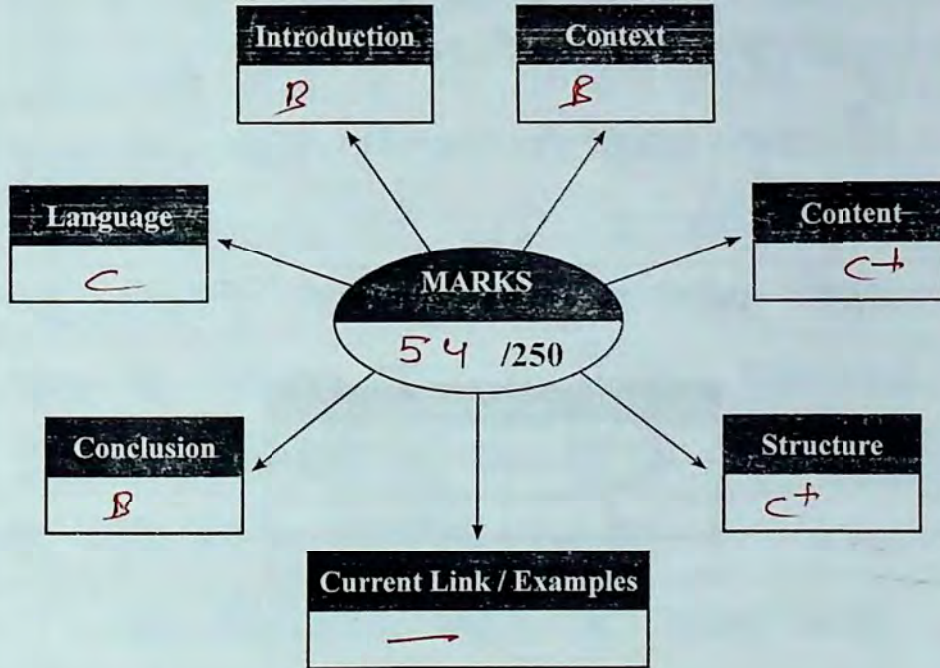
रोल नं. [यूपी.एस.सी. (प्रा.) परीक्षा-2017] [Roll.No. UPSC (Pre) Exam-2017]:

0 5 0 6 0 7 3

परीक्षा का माध्यम (Medium of Exam): हिन्दी  
विद्यार्थी के हस्ताक्षर (Student's Signature): Arvind

नोट: प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश अंतिम पृष्ठ पर संलग्न हैं।

## Evaluation Analysis







## व्यापक विश्लेषण / Macro Analysis

• सभी प्रश्नों को हल करें।

• विषय कलत्र को ध्यान से उन्नत करें।

Grade Card	
Grade 'A'	Very Good
Grade 'B'	Good
Grade 'C'	Satisfactory
Grade 'D'	Poor





कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

1. "भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अब सत्य को खोजने की बजाय व्यावसायिक हितों से निर्देश प्राप्त कर रहा है।" उपर्युक्त कथन का 'पेड-न्यूज़' की पृष्ठभूमि में आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये तथा जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के संबंध में अपने सुझाव भी दीजिये। (250 शब्द) 12.5

"The fourth pillar of Indian democracy is now being guided by commercial considerations rather than pursuit of truth". Critically examine the above statement in the background of paid news and also add your suggestions in reference with the Representation of the People's Act, 1951. (250 words) 12.5

विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ-साथ मीडिया को लोकतंत्र के स्तंभों के रूप में कल्पित किया गया है। भारतीय संविधान के अनु. 19 (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता), जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 और स्वनियमन की आजादी जैसे प्रावधानों के माध्यम से मीडिया की स्वायत्तता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। परन्तु इकारीकरण के बाद से ऐसा प्रतीत होने लगा है कि भारतीय लोकतंत्र में व्यावसायिक हितों की ओर भी झुकाव हुआ है। 'पेड-न्यूज़' इसी प्रवृत्ति का परिचायक है। 'पेड-न्यूज़' का अर्थ है धन या अन्य किसी प्रकार के लाभवश सत्य को छिपाकर पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग। निवचन के सम्बन्ध में सम्बन्ध में पेड न्यूज़ विशेष चर्चा में रही है। इस प्रवृत्ति के बढ़ने के प्रमुख कारण

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

संक्षिप्त  
लिखें





कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

कृपया संख्या न लिखें।  
(Please don't write anything in this space)

निम्नवत हैं:- 1. व्यावसायिक हित - बड़े व्यावसायिक

धरतों द्वारा भारतीय मीडिया का नियंत्रण

2. मीडिया में बढ़ती एकाधिकारवादी प्रवृत्ति

3. राजनेताओं - व्यापारियों से साँजगाह।

4. नैतिकता का हास

5. प्रशिक्षण का अभाव

6. मीडिया क्षेत्र में स्वनिर्भरता की समस्या

इस परिस्थिति को सुधारने का उपाय

पेड यूज के प्रभावों को भी लिखें -

मीडिया की किश्कियनीयता

उत्पन्न होने

लोकतांत्रिक

विहारा-तों का

कमजोर होने

① निर्णायक व्यवस्था का गठन - जिसमें सरकार के साथ-साथ मीडिया से जुड़े हितधारकों का प्रतिनिधित्व हो।

② दूसरे के प्रावधान स्पष्ट व बरोर हों।

③ पेड यूज के मामलों में मीडिया के साथ-साथ सम्बंधित व्यापारी व राजनेता को भी दंड मिले।

④ विज्ञापन व समाचार में स्पष्ट अंतर करने के प्रावधान।



641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9  
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356  
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com  
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiiias





कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अनिश्चित कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

① जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के संबंध में सुझाव संपत्ति व अपराधों के ब्यौरी की तरह 'वेड न्यूज' के स्पष्ट प्रावधान थे।

② चुनावी मुद्दों पर विचार-विमर्श से पर एजिट पोल के साथ-साथ प्रोपीनिपन पोल पर भी नियंत्रण है। अन्याय मतदाता प्रभावित

③ निजी मीडिया हाउस के फसकारों को संबन्धील बनाया जाए।

④ विचिन आयोग में शिक्षित विचारण सेल बनाकर जनता से शिकायतें प्राप्त की जायें।

वस्तुतः भारतीय लोकतंत्र की गाड़ी को सुचारु रूप से चलाने के लिए चारों पहियों का समन्वय आवश्यक है। परमत्त चुनौतियों का सामना कर स्वयं मीडिया अपने गौरवशाली अतीत को जारी रख सकता है।

— X —

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।  
(Please don't write anything in this space)

जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के बारे में संक्षेप में चर्चा करें।

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	2	1	0.25	—	0.25	—
Grade	B	B	C	C	—	B	—





कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

2. यद्यपि भारत 'ब्राजील घोषणापत्र' का हस्ताक्षरकर्ता देश है, फिर भी यहाँ सड़क दुर्घटनाओं को राष्ट्रीय संकट कहा जा सकता है, उदाहरण सहित समझाइए। मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2016 का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द) 12.5

Though India is a signatory to 'Brasilia Declaration', the road accidents can be termed as national crisis, illustrate. Examine the Motor Vehicle (Amendment) Bill, 2016. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

कृपया इस संख्या व न लिखें।

(Please answer any other question in this space)

सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मौतों के मामले में भारत का पूरी दुनिया में पहला स्थान है। लगभग 1 लाख से अधिक लोग प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं की बलि चढ़ जाते हैं। 'ब्राजील घोषणापत्र' का हस्ताक्षरकर्ता देश होने के बावजूद भारत इन दुर्घटनाओं में कभी नहीं ला सका है।

यहाँ की जांच कर लें।

ब्राजील घोषणा पत्र क्या है? संघर्ष में नहीं करें।

भारत में सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण निम्नवत हैं-

1. 5% सड़कों पर ही 60% यातायात का भार (विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्गों पर)
2. ओवर स्पीडिंग (40% दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार)
3. एल्कोहल का सेवन, रोड-रेज
4. रोड की डिजाइनों में कमी
5. ड्राइविंग प्रशिक्षण का अभाव। प्रायः लाइसेंस भ्रष्टाचार के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं।





कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

1 लाख से अधिक मौते प्रतिवर्ष - इस आँकड़े की तुलना मलेरिया, एडस जैसी बीमारियों से करें तो इसे भी राष्ट्रीय संकट कहा जा सकता है। इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले व्यक्ति प्रायः युवा व परिवार के आर्थिक आधार होते हैं। इस प्रकार यह सामाजिक क्षति होती है।

मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2016

- ① इस क्षेत्र के लिए प्रियाभक्त का प्रस्ताव
- ② दुर्घटनाओं में कमी लाने का लक्ष्य
- ③ रोड डिजाइनिंग में सुधार
- ④ जुमाने व फंड में बढ़ोतरी
- ⑤ हाइवे पर डेडवेटेड सेवाओं का गठन जैसे पुलिस व स्वास्थ्य।

विधेयकों की रूपरेखा तैयार करें -

- मोटरवाहन दुर्घटना निधि की स्थापना
- लैप बर्ग वाहनों की कापसी

युवाओं को भी लिखें।

उपरोक्त प्रावधानों से निश्चय ही होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। पर इसके साथ-साथ तकनीकी

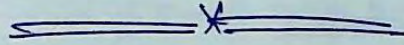




कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

का प्रयोग, जागरूकता - अभियान व प्रशिक्षण जैसे सामाजिक प्रयासों की भी आवश्यकता है। ताकि हम जनसौख्यिकीय लाभों को सड़क पुर्णतयाओं की बलि न चढ़ने दें।



3

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।  
(Please don't write anything in this space)

कृपया इस संख्या के न लिखें।  
(Please don't write anything in this space)

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	1	1	0.25	→	0.25	
Grade	B	C	C	C	—	B	





कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

3. हाल ही में भारतीय सेंसर बोर्ड फिल्मों की पूर्व-सेंसरशिप के लिये चर्चा में रहा। क्या इस तरह की सेंसरशिप स्वामित्व (कॉपीराइट) और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है? इसके विवादित पक्षों पर प्रकाश डालिये तथा भारतीय सिनेमा की समग्रता तथा भारत की विशिष्ट संस्कृति के संबंध में अपने सुझाव दीजिये। (250 शब्द) 12.5

Recently censor board of India was in news for pre censorship of films. Is pre censorship violates copyrights and fundamental rights. Highlight the areas of controversy and put your suggestions for integrity of Indian cinema and ethnicity of Indian culture. 12.5 (250 words)

सेंसरशिप सिद्धांत रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक मर्यादों के बीच संतुलन का वैधानिक प्रयास है। परन्तु भारतीय समाज की विविधता और परम्परा-प्राथुमिकता के मह्य के तनाव ने इस समस्या को और जटिल बना दिया है। फिर वैधानिक बोर्ड के अलावा निजी स्टाफों और समूहों की तरह से भी सेंसरशिप के प्रयास दिखाई दिए हैं।

इस प्रकार के पूर्व-सेंसरशिप के प्रयास वस्तुतः अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (आनु. 19 (1))

और विशेषकर सृजनात्मक अभिव्यक्ति के विरुद्ध हैं। इस तरह के प्रयास मौलिक अधिकारों के साथ-साथ निजी कॉपीराइट का भी एक सीमा तक उल्लंघन करते हैं।

इन प्रयासों में सत्ताधारी दल की

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

भारत में सेंसरशिप की शुरुआत की पूर्व श्रुति को संक्षेप में लिखें।





कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

कृपया इस स्थान में संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please write anything in this space)

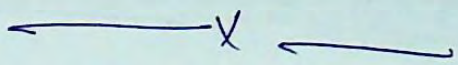
कैसे यह कॉपी राइट का उल्लेख नहीं करते?

विचारधारा का दबाव, व्यक्तिगत प्रवृत्तियाँ, धार्मिक संस्कार जैसे कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आज के समय में जब इंटरनेट पर अभिव्यक्ति की असंयमित आजादी का वातावरण बन रहा है तो ऐसे प्रयासों को विशेष प्रोत्साहन का सापना करना पड़ता है। निजी समूहों द्वारा भी पदमावही फिल्म का सेट जलाना या बिना किसी सरकारी इजाजत के पाकिस्तानी कलाकारों वाली फिल्मों का विरोध भी इस सम्बंध में उल्लेखनीय है।

अतः यह आवश्यक है कि प्रांतीय सर्वोच्च न्यायालय और बोम्बे उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सेंसर-बोर्ड अपनी सामाजिक भूमिका का निर्वाह करते हुए भी पूर्व सेंसरशिप से बचे और फिल्मों की U, A, U/A जैसी श्रेणियों के वर्गीकरण को महत्त्व दे। इस प्रक्रिया से जुड़े लोगों को बदलते समाज को भी ध्यान में रखना होगा।

सुमावों को भी कता है।

3 1/2







कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	1/2	1	0.25	—	0.25	—
Grade	B	C	C	C	—	B	—



कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

4. "संविधान संसद को शक्तियाँ और उन्मुक्तियाँ प्रदान करता है तथा संसद संविधान में संशोधन कर सकती है।" इस कथन को पृष्ठभूमि में रखते हुए क्या आप सोचते हैं कि संसद के कामकाज के नियंत्रण तथा इसे सुगम बनाने के लिये एक निगरानी आयोग की आवश्यकता समय की मांग है? (250 शब्द)

12.5

"The Constitution provides powers and immunities to the Parliament and the Parliament can amend the Constitution". In the background of above statement, do you think a monitoring commission is the need of the hour to control and facilitate the functioning of the Parliament? (250 words)

12.5

भारतीय राजव्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है और संविधान प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत ही विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कार्य करती है। संसद ही संविधान संशोधी शक्तियों के सम्बंध में हमारी व्यवस्था में एक लम्बी दूरी तय की है, जिस यात्रा में निम्न बातों को मील का पत्थर माना जा सकता है -

1. सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1950)
2. चम्पाकम देशीरामन नाद (1951)
3. गोलकुण्ठा बनाम पंजाब राज्य (1967)
4. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)
5. मिखा मिक्स नाद (1980)

तथ्यों की जांच कर लें।

संसदीय विशेषाधिकार कया हैं संकेंद्रित तथ्यों के साथ की जांच करें।

आज स्थिति यह है कि संसद संविधान में ऐसे सभी संशोधन कर सकती है जो आधारभूत ढाँचे को प्रभावित न कर सकते हों। 'न्यायिक पुनरीक्षा' की शक्ति आधारभूत ढाँचे का रक्षण है। इस पृष्ठभूमि में निगरानी आयोग की





कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

स्थापना से संभव है कि संसद व न्यायपालिका में संवाद-स्थापना हो, विशेषज्ञों की निगरानी में तालों पर विचार हो और नए परिवर्तनों की प्रतिक्रिया में नहीं प्रकृत उससे पूर्व ही संसद विधि निर्माण में सहमत हो।  
परन्तु मेरी राय में ऐसी निगरानी के नकारात्मक परिणाम अधिक होंगे -

- ① शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध
- ② संसदीय कार्यवाही में बाधा
- ③ स्वयं संविधान में ही संसद की सीमाओं का निर्धारण के विरुद्ध
- ④ यह एक अलग सांविधिक निकाय बन जाएगा।
- ⑤ संसद में जनता के विश्वास में कमी।

इस प्रकार ऐसे निगरानी आयोग की स्थापना से बेहतर होगा कि संसद व न्यायपालिका अपनी-अपनी सीमाओं को जानकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपना योगदान दे ताकि न्यायिक नियुक्ति आयोग संबंधी संशोधन

निगरानी  
आयोग  
क्यों  
आवश्यक  
हैं स्पष्ट  
उल्लेख  
करें

संविधान  
में  
किए  
गए  
रक्षक  
आयोग  
को भी  
बताएँ।

→ संसदीय  
समिति  
CAG







कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

जैसी समस्या पुनः लोकतंत्र के सम्मुख न आए। भारतीय संसद और व्यापारिका परिषद संस्थाएँ हैं और पक्षर सम्मान व सम्बन्ध से वे सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं।

— X —

2

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।  
(Please don't write anything in this space)

कृपया इस संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।  
(Please don't write anything in this space)

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	0.5	0.5	0.25	-	0.25	
Grade	B	D	D	C	-	B	







कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

5. कुछ राज्यों और क्षेत्रों को प्राप्त विशेष दर्जा अधिक जनआंदोलनों को भड़काने का काम करता है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 12.5
- The special status to some states and certain regions provoke more mass agitation. Critically examine. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370  
 और अनु. 371 में कश्मीर सहित असम, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, आंध्र-कर्णटक, विदर्भ-मराठवाड़ा जैसे क्षेत्रों व प्रदेशों के लिए विशेष प्रावधान करता है। इन प्रावधानों से इनके स्वायत्तता, और केंद्रीय स्वायत्तता मिलती है।  
 ऐसे प्रावधानों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के परिणाम सामने आए हैं।

सकारात्मक

1. विश्वास-बहाली
2. क्षेत्रीय विकास
3. राज्य के साथ-साथ केंद्रीय प्रपद
4. क्षेत्रीय व जनजातीय क्षेत्रों के हितों की रक्षा (जैसे अनुसूची 5 और 6 के तहत)

अन्य वि-दुओं की चर्चा करें।

नकारात्मक परिणाम

1. क्षेत्रीयतावादी प्रवृत्तियों का उभार

केन्द्रीय सहायता का कड़ा हिस्सा प्राप्त करना



कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

2. स्वायत्तता के माध्यम से अनगाववासी प्रकृतियों को प्रांग मिलता है (जैसे - गार्लैंड व परिपुर)

3. नाभों को देखते हुए ग्राम क्षेत्रों में भी ऐसी प्रकृति देखने को मिलती है, जैसे गोरबालैंड की प्रांग।

संसाधनों का  
हक  
सही का  
की  
भारत  
का  
विकास

4. ऐसे क्षेत्रों में जतीय संघर्ष की संभावना जैसे बृहत्तर मंगलम की प्रांग।

क्षेत्रीय राजनैतिक दलों का अद्वय, जो राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से इतने प्रभावी सिद्ध नहीं हुए हैं।

अतः आवश्यक है आवश्यकताओं का समुचित अध्ययन करने के बाद ही ऐसे प्रावधान किए जाएं। ये प्रावधान अस्थायी स्वरूप के हों और जनता की आशंकाओं के निश्चिन्त होने पर प्रावधान समाप्त कर दिए जाएं। जनता की प्रसिद्धि के लिए किए गए विकास कार्यों की समय-समय पर समीक्षा की जाए और उन्हें

प्रभावी  
निष्कर्ष  
लिखें।

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)





कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

जनता के समस रखा जाए (संसद के भाष्य से)। विशेष राज्यों को राजनीतिक महत्वाकांक्षा का साधन न बनने दिया जाए।

————— X —————

4½

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	2	1½	0.25	✓	0.25	-
Grade	B	B	C	C	✓	B	-





कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

6. (a) आम लोगों को त्वरित न्यायिक सेवाएँ प्रदान करने के लिये अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन समय की आवश्यकता है?

6

The creation of All India Judicial Services (AIJS) is the need of the hour for providing fast judicial services to the common people.

6

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

कृपया संख्या न लिखें। (Please don't write any question number in this space)

संविधान के अनु. 312 के अनुसार राज्यों के माध्यम से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता। न्यायपालिका पर बढ़ते काम के बोझ, प्रतिभागियों के पलायन, भाई-भतीजावाद के आरोपों, उच्च पदों की विशिष्ट आवश्यकताओं और एकीकृत न्यायपालिका के स्वरूप को और स्थिर रखने के लिए आज अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन समय की आवश्यकता है। इसके माध्यम से न्यायिक सेवा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

ऐसी सेवा के गठन से जनपद स्तरीय पदों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक अखिल भारतीय स्वरूप का निर्माण होगा और निपुणता में पारदर्शिता आएगी।

न्यायिक निपुणता आयोग के विवाद को देखते हुए संसद द्वारा अध्याय के बाढ़ संघ

अन्य  
लक्ष्यों  
को लिखें  
जैसे -  
राज्यीय न्याया  
मंत्रालय से



641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9  
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356  
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com  
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

एक-समान सेवा-शर्तों को सुनिश्चित करेंगे।





कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

लोकसेवा आयोग जैसी संस्था के माध्यम से रसका चयन कर आम लोगों तक आप पहुंचाने में भारतीय न्यायापालिका को सक्षम बनाया जा सकता है।

====X=====

1 1/2

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।  
(Please don't write anything in this space)

यु.जी.सि.को को भी बताएँ।

(b) क्या आप सोचते हैं कि प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में अंधाधुंध बढ़ती न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर रही है? चर्चा करें। 6.5

Do you think mushrooming of administrative tribunals is creating a hurdle in judicial processes? Discuss. 6.5

न्यायालयों में बढ़ते कार्य के बोझ और विशेष क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए न्यायाधिकरणों की परम्परा प्रारम्भ हुई। ज्ञान सेवा सम्बंधी मामलों से लेकर, शेयर मार्केट, दूध-संचार और परिवहन तक न्यायाधिकरणों की व्यवस्था है। ऐसे न्यायाधिकरणों में प्रशासनिक और न्यायिक दोनों प्रकार के

संक्षेप में न्यायाधिकरण के कार्यों को लिखें।



कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।  
(Please don't write anything in this space)

कृपया संख्या न लिखें।  
(Please don't write any question number in this space)

ग्राह्याधिकारों शामिल हैं।

एक तरफ तो इनसे विशेषज्ञ सेवाएं, कार्पोरेट के बोर्ड का बैठवारा, अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध-संसद की भूमिका पर भी कम बोझ तथा बदलते ~~सामान्य~~ सम्बन्ध के अनुसार शासन व्यवस्था को चलाने में मदद मिलती है।

तो इसी तरह इनसे संसद व ग्राह्याधिकारों के कार्य में सहायता होता है, विकास गतिविधियों पर अनावश्यक अवरोध ~~इत्यादि~~ होते हैं (जैसे- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) और कभी-कभी पाथिक प्रक्रिया में बाधा पानी है जोकि निहित स्वार्थ वाले तत्त्व विभिन्न संस्थाओं के अलग-अलग अधिकार क्षेत्रों का लाभ उठाते हैं।

इस प्रकार 'ग्राह्याधिकारों' के ~~अधिकारों~~ की लाभप्रदता को देखते हुए उपरोक्त चुनौतियों का समाधान कर लें और सार्थक बनाया जा सकता है।

समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए।  
उनके निर्णय के विरुद्ध SC में अपील का अवसर प्राप्त संख्या में कार्यवाही होना

2

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	0.5	0.5	0.5	-	0.25	
Grade	B	B	B	C	-	B	



कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

7. चुनावों के वित्त पोषण से संबंधित पारदर्शिता में सुधार के संदर्भ में किये गए हालिया उपायों पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिये तथा राजनीतिक दलों की बेहतर जवाबदेही के लिये कौन-से कदम उठाए जाने चाहिये? (250 शब्द) 12.5

Critically comment on the recent measures taken to improve transparency in electoral funding and what steps should be taken for better accountability of political parties. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव सम्बंधी भ्रष्टाचार से ही अधिकांश भ्रष्ट आचरण पैदा होते हैं। इसलिए पिछले वर्षों में जिस प्रकार हमारी व्यवस्था ने बाइबल के प्रभाव को नियंत्रित किया है वैसे ही तत्परता से राज. धरुबल को नियंत्रित करने की आवश्यकता है।

चुनावों के वित्त पोषण से सम्बंधित पारदर्शिता में सुधार के संदर्भ में हाल में निम्न उपाय किए गए -

① निवचिन बॉण्डो का प्रारम्भ - इनके माध्यम से कॉर्पोरेट वर्ग बैंकों में धन जमा कर बॉण्ड प्राप्त कर सकते हैं और इन्हें राजनीतिक दलों को दे सकते हैं। लाभ - काले धन के प्रयोग में कमी पारदर्शिता में वृद्धि

② राजनीतिक दलों को अब १००० रु० से अधिक

प्रश्न की श्रुतिका लिखें?

पुस्तकियों की श्रुति करें

कुल नगरी शांत करने की कोई उबरी सीमा नहीं

अन्य लाभों को बताएं।





कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।  
(Please don't write anything in this space)

कृपया संख्या न लिखें।  
(Please don't write any question number in this space)

के चन्दे की राशि का हिसाब रखना पड़ेगा।  
(फरले पद सीमा बीस हजार रू० की)

राजनैतिक दलों की बेहतर स्वाबदेही के लिए निम्न प्रपाथ भी किए जा सकते हैं:-

1. राजनैतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना के प्रयास.
2. चुनाव सम्बंधी उपभेक्षण को विलतारित करना अभी लगभग सभी बड़े प्रत्यासी प्रस्तावित सीमा से अधिक खर्च करते हैं।
3. सीमित रूप में राज्य विलीयन।
4. राजनैतिक दलों को प्रचना के अधिकार के अंतर्गत लाना।
5. राजनैतिक नेताओं और पदाधिकारियों का अंतर करते हुए कार्यपालिका सदस्यों की संपत्ति का तुलनात्मक अध्ययन समथ - समथ कर जाना।  
इन प्रयासों से राजनैतिक दलों की स्वाबदेही बेहतर होगी।

9

निर्कर्ष - प्रानी लिखें।







कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	2	1	0.25	X	0.25	X
Grade	B	B	C	C	X	B	T



कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

8. यह देखा गया है कि काला धन खपाने के लिये अचल संपत्ति मुख्य क्षेत्रों में से एक है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये कि कैसे हाल ही में लागू किये गए अचल संपत्ति विनियमन विकास अधिनियम (RERA) से भ्रष्टाचार को रोकने और उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा में मदद मिलेगी? (250 शब्द)

12.5

It is observed that real estate is one of the main domains of placing black money. Critically analyze that how recently adopted RERA (Real Estate Regulation and Development Act) will help in curbing corruption and protecting consumer rights. (250 words)

12.5

भारत में अचल संपत्ति के बेनामी स्वरूप और संपत्ति के दायों में लगातार वृद्धि के कारण अचल संपत्ति काला धन खपाने के लिए मुख्य क्षेत्रों में से एक है। नोटबंदी के बाद नकद में काला धन रखने की प्रवृत्ति में भी सामाजिक कमी आ रही।

इस दृष्टि से अचल संपत्ति विनियमन विकास अधिनियम (RERA) द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने और उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा में निम्न रूप से मदद मिलेगी।-

- ① नकद लेन में कमी। अब जैसे भी २ लाख से अधिक लेने-देने नकदी में प्रतिबंधित।
- ② स्वतंत्र निष्पक्षकों की स्थापना।
- ③ ७०% राशि अलग बैंक खाते में रखनी होगी। इससे धन को ट्रेस किया जा सकेगा।

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

शान्ति  
की  
रूप  
चर्चा  
करें।

रियल  
एस्टेट  
नियामक  
आधिकारण  
की  
स्थापना





कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या को अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

4 शिक्षापत्र निवारण प्रणाली।

8 एक व सुमति का प्रावधान। यदि विक्रेता या  
क्रेता दोनों में से कोई भी विक्रय-पत्र की  
शर्तों का उल्लंघन करता है।

6 इस संस्करण में पारदर्शी व्यवस्था की स्थापना  
होगी।

7 कृत्रिम रूप से बड़े दामों में कमी आएगी,  
जैसा कि नोडबंदी के बाद देखा गया है।

इन प्रणालियों से 2022 तक सभी के  
लिए आवास मिशन को प्राप्त करने में  
प्रवण मदद मिलेगी।

प्रभावी  
निष्कर्ष दे।

2

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

विक्रेता  
के  
कमियों  
का

भी

उल्लेख  
कों जैसे-

• RERA  
काली  
में

गठन  
करने वालों  
पर  
मान है।





कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	1	0.5	0.25			
Grade	B	C	D	C			

**दृष्टि**  
The Vision

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9  
 दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356  
 ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com  
 फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias



कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

9. अनुच्छेद 142, पूर्ण न्याय के नाम पर किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय को एक प्रभावकारी अधिकार प्रदान करता है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 12.5
- Article 142 provides Supreme Court a virtual license to intervene in any matter in the name of complete justice. Critically analyze. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

अनुच्छेद 142 के अन्तर्गत 'पूर्ण न्याय' प्रदान करने के लिए, समक्ष आए किसी भी मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश और डिस्क्रि संसद द्वारा विहित रीति से भारत के राष्ट्र क्षेत्र में लागू होंगे।

स्पष्ट लिखें

- इसके प्रयोग से दिए गए कुछ आदेश विवाद व चर्चा का विषय रहे हैं - जैसे
- राष्ट्रीय राजमार्ग से 800 मी की इरी तक शराब की दुकानों को बंद करना।
  - पपविण सम्बंधी मामलों में निर्देश।

कुछ अन्य निर्णयों का भी उल्लेख करें।

सकारात्मक पक्ष

1. लोगों को पूर्ण न्याय मिलना
2. न्यायालय की सामाजिक जवाबदारी की भूमिका

विस्तार से लिखें।

कारणात्मक पक्ष

1. न्यायिक प्रतिबद्धता
2. संसद व कार्यपालिका के कार्य में हस्तक्षेप





कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

3. इन क्षेत्रों में 'ग्यापालपो' द्वारा आड़े हाथों देना जिनमें ग्यापालपो की विशेषज्ञता नहीं है।

4. एक क्रिच के अन्य सामाजिक प्रभावों को ध्यान में न रखना, जैसे - रोजगार, कानून व्यवस्था।

अतः ग्यापालपो को अनुच्छेद 142 द्वारा पदोन्नत अधिकार का प्रयोग संसद द्वारा विहित शक्ति से और विधायिका व कार्यपालिका की सीमाओं व शक्तियों का सम्मान करते हुए करना चाहिए। पक्षी लोकतंत्र की शक्ति का आधार है।

3

————— X —————

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

कृपया संख्या न लिखें। (Please don't write any question number in this space)





कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	—	1 1/2	1	0.25	—	0.25	2
Grade	—	C	C	C	—	B	2



कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

10. एक ऐसा देश जहाँ के अधिकांश नागरिक सरकार की नीतियों तथा सरकार के कामकाज को लेकर अनभिज्ञ हैं, वहीं विभिन्न सेवाओं को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर देना मानसिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा। विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 12.5

A country in which most of its citizens are unaware of functioning of government and government policies; mandatory Aadhar card link to various services will create a trauma of confusion, analyze. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

प्रश्न के उत्तर में प्रश्नीय भूमिका लिखें।

हाल के एक सर्वेक्षण में भारत को अपनी सरकार पर भरोसे के लिहाज से पहला देश माना गया है। भारतीय जनता सरकार की नीतियों और कामकाज की गतिविधियों को धले ही न सभसे पर वह लोककल्याणकारी नीतियों के प्रभाव के प्रति अत्यधिक संतुष्ट रहती है।

ऐसे में विभिन्न सेवाओं को आधार से जोड़ने से निम्न लाभ प्राप्त होंगे -

1. सत्सिद्धि पुनिसंगत बनेगी। - लीकेज में कमी
2. लक्ष्यार्थी तक सेवा की पहुँच।
3. सरकार को अपनी योजनाओं के विस्तार और प्रभाव का डेटा मिलेगा।
4. भ्रष्टाचार व धोखाधड़ी में कमी।
5. सरकारी कर्मचारियों की क्षमिता भूमिका।
6. फुलप्रूप होने के बाद सामाजिक योजनाओं में निजी क्षेत्र को शामिल किया जाता है।

डिजिटल  
लॉकर  
जोखना  
सम्भव  
कर-बोरी  
को  
रकने में  
मदत

आदि की



कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

## संज्ञियाँ

- त्रिजला का रजम
- बोगों की तकनीकी तक पहुँच न होना।
- डेरा झोर लारबर सुरक्षा का अंतर।
- सरकार में सत्ताधारी दल की भूमिका पर निर्भरता ~~बढ़ती~~ बढ़ती।
- तानशाही प्रवृत्तियों में ऐसा दल संकेंडीकरण मद्दगार सिद्ध हो सकता है।

ऐसे में यह अधिक उचित प्रतीत होता है कि डेरा संरक्षण के प्रावधान कर, त्रिजला को सुरक्षित रखते हुए आधार के उपयोग को प्रारम्भ में इन्हीं क्षेत्रों तक सीमित लेकर देखा जाए, जहाँ तक सर्वोच्च गणतंत्र की प्रवृत्ति मिली है। तदुपरांत सुधारों के साथ इसका वित्तर अधिक विवेकपूर्ण होगा।

— X — (4)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

अल्प  
संज्ञियों  
को  
श्री  
लिखें





कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।  
(Please don't write anything in this space)

कृ  
सं  
न  
(P  
an  
qu  
th

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	2	1.6	0.25	2	0.25	
Grade	B	B	C	C	A	B	<input checked="" type="checkbox"/>



641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9  
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356  
ई-मेल: [helpline@groupdrishiti.com](mailto:helpline@groupdrishiti.com), वेबसाइट: [www.drishtilias.com](http://www.drishtilias.com)  
फेसबुक: [facebook.com/drishtithevisionfoundation](https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation), ट्विटर: [twitter.com/drishtilias](https://twitter.com/drishtilias)





कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

11. हाल ही में महिला श्रम बल भागीदारी को लेकर एनएसएस के आँकड़ों में प्रदर्शित किया गया है कि नगरीय क्षेत्रों में महिला श्रम बल की भागीदारी स्थिर हो रही है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें गिरावट आ रही है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 12.5

Recent NSS data on women labour force participation has shown that women labour participation is stagnated in urban areas and sharply declining in the rural areas. Critically examine. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

उदारीकरण के बाद से महिला श्रम बल की भागीदारी बढ़ने की प्रवृत्ति देखी गई है। हाल के वर्षों में नगरीय क्षेत्र में महिला श्रम बल की भागीदारी स्थिर हो रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में गिरावट के निम्न कारण प्रदर्शित किए जा सकते हैं:-

1. रोजगार के कुल अवसरों में घा रही कमी - रोजगारविहीन शक्ति।
2. कम अवसर होने से पुरुषों द्वारा उभर प्रतिस्पर्धा
3. सेवा क्षेत्र की संवृद्धि पर का पहले की तुलना में धीमा होना (वैश्विक कारणों से) पछी प्रवृत्तियाँ जहाँ रोजगार प्राप्त करती थीं।
4. ग्रामीणों में तकनीक का बढ़ता प्रयोग, जिससे मानव श्रम बल की मांग कम पड़ रही है।
5. स्कूली शिक्षा और कौशल विकास की घोर

ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल में गिरावट के कारणों का अलग-2 चित्रा आंक में लिखें।

जैसे - ग्रामीण क्षेत्रों -

स्वातंत्र्य स्तर पर रोजगार का





कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

बहुता रुझान।  
 रिपल स्ट्रेट सेक्टर में मंदी - निम्निय उद्योग धीमा।  
 इनमें से नकारात्मक कारणा के संप्राधान के लिए विनिर्माण क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रवसर बोझने होंगे क्योंकि शिक्षित व कुशल लोगों की (धुफ़ों सहित) सपना का लाभ डाक़र ही भारत समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।

अन्य  
 प्रश्नों  
 को  
 भी  
 लिखें।

॥

• उच्च-कृषि कार्यो

के संज्ञन की आवश्यकता

• सरकारी नीतियो द्वारा सामाजिक

मान्यताओं को हट करना

आदि।

2





स्थान में  
नहीं।  
Don't write  
in this space)

कृपया इस स्थान में प्रश्न  
संख्या के अतिरिक्त कुछ  
न लिखें।  
(Please do not write  
anything except the  
question number in  
this space)

कृपया इस स्थान में  
कुछ न लिखें।  
(Please don't write  
anything in this space)

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	1	0.5	0.75	_____	_____	_____
Grade	B	C	D	C	_____	_____	_____



641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9  
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356  
ई-मेल: [helpline@groupdrishti.com](mailto:helpline@groupdrishti.com), वेबसाइट: [www.drishtiIAS.com](http://www.drishtiIAS.com)  
फेसबुक: [facebook.com/drishtithevisionfoundation](https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation), ट्विटर: [twitter.com/drishtiias](https://twitter.com/drishtiias)



कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

12. प्राचीन काल में धर्मनिरपेक्षता भारतीय समाज का महत्वपूर्ण विशेषता थी। हाल ही में धर्मनिरपेक्षता शब्द को समाचार माध्यमों में लगातार उछाला जाता रहा है। इस संदर्भ में वर्तमान परिदृश्य का विश्लेषण कीजिये, क्या भारत में धर्मनिरपेक्षता खतरे में है? चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 12.5

From ancient times secularism was essential feature of Indian society. Recently the term secularism was flaunted continuously in media news. Analyze the current scenario in this regard; is secularism in India at risk? Discuss. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।  
(Please don't write anything in this space)

पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से पृथक भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ मोटे तौर पर 'सर्वधर्म समभाव' रहा है। अर्थात् राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करेगा और किसी विशेष धर्म की प्रशिक्षण के लिए पुंजास नहीं करेगा। (अनु. 25 से 30, अनु. 14, 15, 16)

प्राचीन  
सम्राज्य  
में  
धर्मनिरपेक्षता  
की  
विशेषताओं  
का  
उल्लेख  
करें।

वर्तमान परिदृश्य में कुछ मामलों में ऐसा देखा गया है कि धर्मनिरपेक्षता को नकारात्मक अर्थ में प्रस्तुत कर इसे अल्पसंख्यक उन्मीकरण का समानार्थी बताया गया है। गोमंत्र, लव-जिहाद, -विवाद जैसे मामलों में धर्मों के मानने वालों के बीच दरिपों बड़ी हैं।

वास्तव में प्राथमिक विकास के इन लक्षणों पर भारत यह संकेत मोल नहीं ले सकता।

लव-जिहाद,  
↓  
'लीफ बॅन'  
'श्री 575'  
आदि का  
उल्लेख  
करें।





इस स्थान में लिखें।  
 don't write anything in this space  
 कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।  
 (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।  
 (Please don't write anything in this space)

भारत में धर्मनिरपेक्षता की नई परांपरा के समय से लेकर गांधी तक के उपासकों से गहरे जमी हैं। अतः ऐसी घटनाओं से धर्मनिरपेक्षता खतरे में तो नहीं पड़ेगी पर विभाजनकारी शक्तियों को हवा न देकर मिलती है।  
ऐसे में प्रांभिक शिक्षा से लेकर संसद - न्यायपालिका तक के क्षेत्रों के लिए सतर्क व प्रयासरत रहना चाहिए, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता प्राच्यनिक व विविध भारत की मूलभूत शक्ति है।

धर्म -  
निरपेक्षता  
की  
वर्तमान  
स्थिति  
को  
स्पष्ट  
करें।

निष्कर्ष

को ————— X —————  
 सामग्री लिखें।

3

जिसका  
 वें-  
 डं  
 का



641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9  
 दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356  
 ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com  
 फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias





कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	1/2	1	0.25			
Grade	B	C	C	C			

**दृष्टि**  
The Vision

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9  
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356  
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com  
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtias

38

Copyright - Drishti The Vision Foundation



संस्थान में  
लिखें।  
don't write  
in this space)  
(Please do not write  
anything except the  
question number in  
this space)

13. भारत सरकार अपने नागरिकों की खाद्य-सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रही है लेकिन किसानों की सुरक्षा दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। खाद्य-सुरक्षा की चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये तथा किसानों की स्थिति में सुधार लाने के उपाय भी सुझाइये। (250 शब्द) 12.5
- Indian government is focusing on food security of its citizen but farmer's security deteriorating day by day. Critically examine challenges for food security and also mention suggestion for improvement of conditions of farmers. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में  
कुछ न लिखें।  
(Please don't write  
anything in this space)

किसानों की स्थिति और खाद्य-सुरक्षा  
परस्पर निर्भर हैं। एक के बिना खाद्य दिनों  
तक हमारे की कल्पना नहीं की जा सकती है।

खाद्य-सुरक्षा की प्रमुख चुनौतियाँ

1. उत्पादकता में गिरावट
2. मानसून पर निर्भरता
3. खाद्य-प्रसंस्करण उद्योग का अभाव
4. विकसित देशों की खाद्य-नीतियाँ
5. लगातार छोटी होती जा रहे
6. वृद्धिमान प्राबादी

इसीलिए सरकार ने दूसरी सही सही बातें  
मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नीम बोर्ड प्ररिण, सत्विकी  
परिष्कारण, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना  
और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे प्रयास  
किए हैं।

इन प्रयासों के साथ-साथ किसानों की

किसानों  
की  
सुरक्षा  
क्यों  
आवश्यक  
है कारनों  
के साथ  
स्पष्ट  
चर्चा करें।

इसके कृषि  
श्रमि का  
स्वानांतरण

असम  
परिषद  
मंगली

विकसित

39 कृषि

बैंकिंग से

का प्रभाव  
etc)



कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

स्थिति में सुधार लाया भी जरूरी है जिसके लिए आवश्यक है कि -

- संस्थागत वित्त की पहुँच बढ़ाई जाए।
- उत्तम क्षमता वाले लोगों का पाठ्य बहाल जाए
- विद्यार्थियों के प्रशिक्षण में सुधार।
- नकदी फसलों को क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार ही प्रोत्साहित हो।
- मिश्र शिक्षण व पशुपालन को बढ़ावा।
- गांवों में शिक्षा व स्वास्थ्य में निवेश बढ़े।
- कृषि में लगे अतिरिक्त श्रमबल के लिए उद्योगों में रोजगार के अवसरों का सृजन व समता निर्माण।

इससे प्राप्त प्राप्ति से हम अपने अभावों को दूर करने में स्थिति में सुधार भी लाएंगे और जाय-सुरक्षा भी सुनिश्चित करेंगे।

— X —

(3½)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)





इस स्थान में लिखें।  
don't write anything in this space

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।  
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।  
(Please don't write anything in this space)

*[Faint handwritten text in Hindi, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	1 1/2	1	0.25	-	0.25	A
Grade	B	C	C	C	-	B	S





कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

14. भारत में एकल परिवार का प्रचलन संयुक्त परिवार से अधिक होता जा रहा है क्योंकि भारतीय समाज समूह की अपेक्षा व्यक्तिवाद की ओर अधिक आकर्षित हो रहा है। चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

12.5

Trends of nuclear family in India are more common than joint family as Indian society is heading towards more individualism than community. Discuss. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

भारत में परम्परा से ही परिवार को समाज की रूढ़ि के रूप में मान्यता मिली है परंतु पिछले कुछ दशकों में संयुक्त परिवार के स्थान पर एकल परिवार का प्रचलन बढ़ा है। वस्तुतः इस प्रकृतिगत बदलाव के पीछे समाज की अपेक्षा व्यक्तिवाद की ओर अधिक प्रवर्तन एक कारण है।

पर इस प्रकृतिगत संवर्धन के प्रतिरिक्त भी एकल परिवार की प्रकृति के बढ़ने के निम्न कारण हैं:-

- ① कार्य के विशेषीकरण से पलायन - गाँव शहर व विकसित क्षेत्रों की ओर।
- ② शहरों में मंडगाई व छोटे प्रकाश।
- ③ गाँवों में जमीनों की देखभाल के लिए किसी का शकना।
- ④ जीहीगत अंतराल



इस स्थान में  
लिखें।  
don't write  
in this space

कृपया इस स्थान में प्रश्न  
संख्या के अतिरिक्त कुछ  
न लिखें।  
(Please do not write  
anything except the  
question number in  
this space)

8) आधुनिक प्रवृत्तियों का प्रचलन

6) निजी स्पेस की प्राप्ति

क) दूर रहकर भी परिवार से सम्बंध रख पाने की तकनीक व सुविधाएँ बढ़ रही हैं।

8) शहरी संस्कृति में सामूहिकता का अभाव।

9) फ्लैट संस्कृति में एक दूसरे से मिलने-जुलने के कम अवसर।

संपुस्त परिवार का विघटन क्रमशः धीरे-धीरे हुआ है। जिससे बच्चों व वृद्धों पर विशेष नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। इसलिए आवश्यक है कि सरकार शहरों में कम से कम तीन पीढ़ियों के साथ में रहने की संस्कृति को प्रोत्साहन और बच्चों के लिए व वृद्धों के लिए विशेष कल्याणकारी स्थापना अपनाने।

← X ←  
4

कृपया इस स्थान में  
कुछ न लिखें।  
(Please don't write  
anything in this space)

कारणों  
की  
इससे स्पष्ट  
वर्गीकरण  
जैसे -

- विवाह व्यवस्था में परिवर्तन
- पारिवारिक संस्कृति का प्रभाव
- महिलाओं का आर्थिक स्वतंत्रता
- अचार एवं परिवार का प्रभाव आदि।





कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	2	1	0.25	X	0.25	✓
Grade	B	B	C	C	X	B	✓



641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9  
 दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356  
 ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com  
 फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiiias





इस स्थान में लिखें।  
 कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।  
 (Please do not write anything except the question number in this space)

15. हमारी शिक्षा प्रणाली बड़े राजनीतिक समुदाय के रूप में ग्रामीणों को एकीकृत करने में असफल रही है। टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द) 12.5

Our education system has failed to integrate the rural into the larger political community. Comment. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।  
 (Please don't write anything in this space)

अक्सर कहा जाता है कि इस देश में 'ग्रामीण भारत' और 'शहरी इंडिया' साथ-साथ गतिमान हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली के वर्गीय चरित्र ने अभी तक इस भेदभाव को मिटाने के अभी तक तो कोई सहायनीय प्रयास नहीं किए हैं।

इससे विकास के अधिकांश अवसरों से ग्रामीण समाज वंचित रहा है। साथ ही साथ राजनीतिक चेतना के विकास में भी ग्रामीण समाज पिछड़ता गया है। आज स्थिति यह है कि संसदात्मक में अधिक सीटों के बावजूद ग्रामीण भारत लोकतंत्र के लाभ प्राप्त करने में पीछे है।

यह कहना तो सही नहीं होगा कि ग्रामीण भारत राजनीतिक रूप से संगठित नहीं है। प्रकृत सच यह है कि प्रागैतिहासिक और आधुनिक शिक्षा के अभाव में आज में ग्रामीण भारत

भारत में शिक्षा प्रणाली की पहलुओं की चर्चा करते हुए यह स्पष्ट करें कि यह क्यों ग्रामीणों की एकीकृत करने में अलफल रही





कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

में धर्म, जाति, मर्यादा, समुदाय का महत्व है और शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, प्रदर्शन, पारदर्शिता जैसे मुद्दे परिदृश्य से प्रोत्साहित हैं।

ज्ञानमय  
संज्ञा  
के  
द्वारा  
की  
वर्तमान  
महत्ता  
का उल्लेख  
की।

जिससे राजनीतिक एकीकरण का लाभ उन्हें वास्तविक स्तर में नहीं मिल पाता। प्रगतिशील और आधुनिक शिक्षा के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाना संभव है।

2 1/2



641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9  
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356  
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiAS.com  
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiiias





इस स्थान में  
लिखें।  
Please do not write  
anything except the  
question number in  
this space

कृपया इस स्थान में  
कुछ न लिखें।  
(Please don't write  
anything in this space)

*[Faint handwritten text in Hindi, mostly illegible due to blurriness]*

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	1	0.5	0.25	A	0.25	
Grade	B	C	D	C		B	



641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9  
 दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356  
 ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com  
 फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtias



कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

16. यह माना जाता है कि विमुद्रीकरण नकदी-विहीन समाज को प्रेरणा देकर कल्याणकारी कार्यक्रमों को बढ़ावा देगा। विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों की विफलताओं की पृष्ठभूमि में इस कथन पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

12.5

It is believed that the demonetization will provide thrust to the welfare programmes by providing stimulus to cashless society. Discuss this statement in the backdrop of failures of various welfare programmes. (250 words)

12.5

अनु 38 और 39 में उल्लिखित

कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य की ओर भारत ने 1980 से ही यात्रा प्रारम्भ कर दी थी। पर इस क्षेत्र में प्रगति धीमी ही रही।

जैसे-जैसे हम नकदी-विहीन समाज की ओर बढ़ेंगे, वैसे-वैसे विभिन्न

कल्याणकारी कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी और अधिक सफल बनाना सम्भव होगा। तकनीक के उपयोग के प्रभाव निम्नवत होंगे

संक्षेप में भारत में कल्याणकारी योजनाओं

1. लीकेज में कमी - डापरेन्ट लेनिफिट ट्रांसफर
2. लक्षित व्यक्ति तक सामान व सेवा की सुविधा
3. भ्रष्टाचार व धोखाधड़ी में कमी
4. सरकार को अपनी योजनाओं के प्रभाव की जातकरी
5. वित्तीय समन्वयन - जन-धन योजना
6. जन-धन - आधार - भोवसल मॉडल (JAM Trinity)
7. आवासीय लाभार्थियों की शपथ

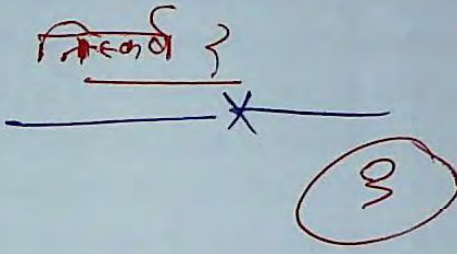




इस स्थान में  
लिखें।  
(Please do not write  
anything except the  
question number in  
this space)

कृपया इस स्थान में  
कुछ न लिखें।  
(Please don't write  
anything in this space)

7. का इसी संघर्ष में उल्लेख किया गया था  
सरकारी धवसंरचना पर कप्त बोसा  
8. सरकार बाजार में हस्तक्षेप से बच सकती है



अ-य  
मन्त्राको  
को लिखें।  
↓  
-आशाली  
लाभार्थियों के  
उ-मुक्तता है  
ल कारी वर्णों का  
विवेकपूर्ण उपयोग





कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	1/2	1	0.25			
Grade	B	C	C	D			

**दृष्टि**  
The Vision

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9  
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356  
ई-मेल: helpline@groupdrishiti.com, वेबसाइट: www.drishitiIAS.com  
फेसबुक: facebook.com/drishitithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishitiias

50

Copyright - Drishiti The Vision Foundation



कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

18. किसानों की कृषि ऋण माफी केवल अस्थायी राहत है। उक्त कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये तथा किसानों की स्थिति को सुधारने हेतु उपाय सुझाइये। (250 शब्द) 12.5

Waiving off farm loans is only temporary relief to the farmers. Critically examine above statement and give your suggestions for improving conditions of farmers. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

कृषि  
ऋण  
माफी  
के  
सकारात्मक  
एवं  
सकारात्मक  
पक्षों  
की  
वर्णना  
करें।  
4  
8

किसानों की कृषि ऋण माफी वास्तुतः  
बीमारी के कारणों का नहीं अपितु बीमारी  
के लक्षणों का उपचार करने जैसा है।  
यद्यपि संप्रत्या गहन होने पर ऋण माफी की  
भी जरूरत होती है परन्तु किसानों की  
स्थिति सुधारने के लिए और प्रबारा ऋण  
माफी की जरूरत न पड़ने देने के लिए  
आवश्यक है कि -

1. सरकार कृषकों की आप को दोगुना करने के लक्ष्य पर तीव्र कार्य प्रारम्भ करें।
2. कृषि क्षेत्र की योजनाओं जैसे महा आध्य की पूर्वा. कृषि निगम चो. व. उपलब्धी योजना की विशेष प्राथमिकता।
3. संस्थागत वित्त की पहुँच बढ़ाई जाए
4. अन्ततः सार्वजनिक अर्थों का सहायता बढ़े
5. किसानों को प्रशिक्षण तथा सुझावों की वर्णना करें।





इस स्थान में  
लिखें।

don't write  
g in this space

कृपया इस स्थान में प्रश्न  
संख्या के अतिरिक्त कुछ  
न लिखें।

(Please do not write  
anything except the  
question number in  
this space)

6. कवि पर बौस कन कल 'धोगो' मे  
शेजगाट।
7. भिस्य शास्यत और पशुपालन

2

कृपया इस स्थान में  
कुछ न लिखें।

(Please don't write  
anything in this space)





कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या को अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	1	0.5	0.25	←	←	←
Grade	B	C	D	C	←	←	←



641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9  
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356  
ई-मेल: helpline@groupdrishiti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com  
फेसबुक: facebook.com/drishitithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtilas





इस स्थान में  
लिखें।  
Please don't write  
anything in this space  
कृपया इस स्थान में प्रश्न  
संख्या के अतिरिक्त कुछ  
न लिखें।  
(Please do not write  
anything except the  
question number in  
this space)

19. उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2015; उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान लेगा, इन दोनों की तुलना कीजिये तथा इनमें वैषम्यता दर्शाइये। (250 शब्द)

12.5

The Consumer Protection Bill, 2015 will replace the Consumer Protection Act, 1986, compare and contrast both. (250 words)

12.5

कृपया इस स्थान में  
कुछ न लिखें।  
(Please don't write  
anything in this space)

नवीन अर्थ विधेयक का प्रभाव

निष्पात्र की व्यवस्था

शिक्षित निवेश प्रवर्धनी

उपभोक्ता अधिकारों पर जोर



इस स्थान में  
न लिखें।  
Please don't write  
anything in this space

कृपया इस स्थान में प्रश्न  
संख्या के अतिरिक्त कुछ  
न लिखें।  
(Please do not write  
anything except the  
question number in  
this space)

कृपया इस स्थान में  
कुछ न लिखें।  
(Please don't write  
anything in this space)

- (b) उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2015 का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। 6.5  
Critically examine the Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2016. 6.5

विषयता

- तृतीय लिंग को मान्यता
- विद्वेष वर्ग के सघन आरक्षण
- विज्जा, मारिजा का अधिकार
- उभयलिंगी व्यक्ति को सर्व-स्वतंत्र
- परिवार में रहने का अधिकार

①  
②

विस्तार  
से  
लिखें।

अज्ञान अपूर्ण हैं





कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	—	0.5	—	—	—	—	—
Grade	—	B	—	—	—	—	—

### Feedback

Questions .....

Model Answer & Answer Structure .....

Evaluation .....

Staff .....





रफ कार्य के लिये स्थान  
(Space for Rough Work)

या इस स्थान में  
न लिखें।  
Please don't write  
anything in this space





### प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:  
इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं।  
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।

प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

### QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

*Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:*

*There are TWENTY questions printed both in HINDI and in ENGLISH.*

*All the questions are compulsory.*

*The number of marks carried by a question is indicated against it.*

*Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.*

*Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.*

*Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off*

रफ कार्य के लिये स्थान

(Space for Rough Work)